जून 2022 | वर्ष : 9 | अंक : 4

सभी परीक्षाओं को समर्पित प्रतियोगी पत्रिका

समसामयिकी क्रॉनिकल

इस अंक में...

06 आर्थिकी

- राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक
- फिनक्लुवेशन
- बैटरी अदला-बदली नीति का मसौदा
- गरीबी पर विश्व बैंक शोध पत्र
- गुजरात में नई परियोजनाओं की शुरुआत
- डिजिटल बैंकिंग इकाइयां
- डब्ल्यूटीओ की चेतावनी
- भारत का कृषि निर्यात
- राष्ट्रीय टाइम रिलीज स्टडी 2022
- रेलवे की 'एक स्टेशन एक उत्पाद' पहल
- ड्रोन पीएलआई योजना
- भारत में कोयले की कमी
- भारत की 8% वृद्धि दर का अनुमान
- तमिलनाडु में सीवीड पार्क
- भारत में ग्रामीण मंहगाई दर
- व्यापार सुविधा केंद्र
- राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण
- निधि (संशोधन) नियम 2022
- राष्ट्रीय राजमार्ग प्री-कास्ट कंक्रीट नीति
- बनारसी पश्मीना
- ओबीसी उद्यमी
- बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली
- स्टैंड अप इंडिया योजना की छठी वर्षगांठ
- क्वार जल विद्युत परियोजना

20 राष्ट्रीय

- सीमा दर्शन परियोजना
- प्रधानमंत्री संग्रहालय
- वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में 4जी सेवाएं
- पल्ली बनी भारत की पहली 'कार्बन-न्यूट्रल पंचायत'
- फोर्टिफाइड चावल
- सातवां रायसीना डायलॉग
- ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन
- राष्ट्रीय डेटा और वैश्लेषिकी मंच
- एस-400 प्रशिक्षण उपकरण
- एनआरआई के लिए पोस्टल बैलेट
- कुलपति की नियुक्ति से संबंधित विधेयक
- दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2022
- भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशीकरण
- हनुमानजी4धाम परियोजना
- परीक्षा पर्व 4.0
- संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
- रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में संशोधन
- मिशन वात्सल्य योजना
- अटल इनोवेशन मिशन
- राष्ट्रमंडल संसदीय संघ
- चौथा पोषण पखवाड़ा
- तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची
- अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0
- 'आजादी से अंत्योदय तक' अभियान

34 अंतरराष्ट्रीय

- छठा भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श
- भारत-जर्मनी समझौते
- चीन की वैश्विक सुरक्षा पहल
- दिव्यांगता में भारत और चिली का सहयोग
- लिथुआनिया में नए भारतीय मिशन की मंजूरी
- राष्ट्रपति की नीदरलैंड की राजकीय यात्रा
- भारत-यूएई आर्थिक साझेदारी समझौता
- राष्ट्रपति की तुर्कमेनिस्तान की यात्रा
- विश्व सैन्य व्यय
- इंडोनेशिया का पाम ऑयल संकट
- विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला होंगे जी-20 समन्वयक
- कुरील द्वीप विवाद
- चीन-सोलोमन द्वीप सुरक्षा समझौता

40 विज्ञान-पर्यावरण

- ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2021
- भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन
- भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022
- आईपीसीसी छठी आकलन रिपोर्ट-भाग 3
- इंस्पेक्टआईआर कोविड-19 ब्रीथलाइजर
- भारत का तटीय क्षरण
- स्ट्रोन्शियम: एक साइबर-जासूसी समूह
- डिजिटल इंडिया आरआईएससी-5
- ब्लू स्ट्रैगलर्स
- गेहूं की किस्म 'पीबीडब्ल्यू-1 चपाती'
- पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया
- दुर्लभ तितली पामकिंग
- शुभंकर 'प्रकृति' और हरित पहल
- 'सेमीकॉन इंडिया' कार्यक्रम समिति
- क्वांटम कंप्यूटिंग पर इंडो-फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर
- एवीजीसी संवर्धन टास्क फोर्स
- काजीरंगा पशु गलियारा
- जोनाथन: स्थल पर दुनिया का सबसे उम्रदराज जानवर
- कोविड के खिलाफ भारत निर्मित 'वार्म' वैक्सीन
- हेलिना मिसाइल
- मृदा स्थिरीकरण के लिए तकनीक
- पिनाका एमके-I (उन्नत) रॉकेट सिस्टम
- अभिवृद्धि करने वाले नवोदित तारे
- भारत का सौर क्षमता लक्ष्य

51 राज्य

58 खेल

सार-संक्षेप

- चर्चित व्यक्ति/ निधन..... 63
- नियुक्ति..... 64
- पुरस्कार/सम्मान..... 66
- अभियान/सम्मेलन/आयोजन..... 68
- युद्धाभ्यास/सैन्य अभियान..... 70
- कला/संस्कृति/ समझौते/संधि..... 71
- वेब पोर्टल/ऐप/ बैंकिंग..... 72
- फाइनेंस/बीमा/ बिजनेस/व्यापार..... 73
- सार्वजानिक उपक्रम/ चर्चित पुस्तक/ चर्चित दिवस 74
- वन लाइनर सामयिकी..... 78
- समसामयिक प्रश्न..... 80

81 पत्र-पत्रिका संपादकीय

संपादक: एन.एन. ओझा
अध्यक्ष: संजीव नन्दक्योलियार
उपाध्यक्ष: कीर्ति नंदिता
सहायक महाप्रबंधक: पंकज पांडेय
संपादकीय: 9582948817, cschindi@chronicleindia.in
विज्ञापन: 9953007627, advt@chronicleindia.in
सदस्यता: 9953007629, subscription@chronicleindia.in
प्रसार: 9953007630, circulation@chronicleindia.in
व्यावसायिक कार्यालय: क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.
ए-27 डी, सेक्टर-16, नोएडा-201301
Tel.: 0120-2514610-12, info@chronicleindia.in

क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.: प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार अपने हैं। उनसे संपादक का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है। संपादक की लिखित अनुमति के बिना इस पत्रिका में प्रकाशित किसी भी सामग्री को उद्धृत या उसका अनुवाद नहीं किया जा सकता। पाठकों से अनुरोध है कि पत्रिका में छपे किसी भी विज्ञापन की सूचना की जांच स्वयं कर लें। समसामयिकी क्रॉनिकल, विज्ञापनों में प्रकाशित दावों के लिए किसी प्रकार जिम्मेदार नहीं है। किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

क्रॉनिकल पब्लिकेशंस प्रा.लि. के लिए **प्रकाशक एवं मुद्रक-मृणाल ओझा** द्वारा एच-31, प्रथम तल ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नयी दिल्ली-110016, से प्रकाशित एवं राजेश्वरी फोटोसेटर्स प्रा. लि., 2/12 ईस्ट पंजाबी बाग नयी दिल्ली से मुद्रित- **संपादक एन.एन. ओझा**

आर्थिकी

राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक

नीति आयोग द्वारा 11 अप्रैल, 2022 को राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक-राउंड I का शुभारंभ किया गया।

Score and Ranking of Larger States								
Rank	Statesè-kUTs	Dis-com's Perfor-mance	Access, afford-ability & rellability	Clean Energy Initia-tives	Energy Effi-ciency	Env Sustain-ability	New initia-tives	Secis-core
1	Gujarat	72.7	52.4	39.2	40.1	35.1	5.5	50.1
2	Kerala	64.4	67.3	21.5	58	46.9	7.7	49.1
3	Punjab	77.1	46.8	26.1	35.1	37	2.3	48.6
4	Haryana	69.8	53.6	42.9	11.7	33.4	6.9	47.9
5	Uttara-khand	61.9	55.3	18.5	50.5	48.7	14.7	46.5

सूचकांक के उद्देश्य: ऊर्जा पहुंच, ऊर्जा खपत, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण की सुरक्षा में सुधार के प्रयासों के आधार पर राज्यों की रैंकिंग;

- राज्य स्तर पर सस्ती, सुलभ, कुशल और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के एजेंडे को आगे बढ़ाने में मदद करना;
- ऊर्जा और जलवायु के विभिन्न आयामों पर राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना।

महत्वपूर्ण तथ्य: राज्यों को आकार और भौगोलिक अंतर के आधार पर बड़े राज्यों, छोटे राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को संदर्भ वर्ष (2019-20) के आधार पर तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है- फ्रंट रनर (समग्र स्कोर 46 से अधिक), अचीवर्स (समग्र स्कोर 36 से 46 के बीच) और एस्पिरेंट्स (समग्र स्कोर 36 से कम)।
- गुजरात, केरल और पंजाब को बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष तीन प्रदर्शनकर्ताओं के रूप में स्थान दिया गया है।
- गोवा, छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा, इसके बाद त्रिपुरा और मणिपुर का स्थान है।
- केंद्र-शासित प्रदेशों में, चंडीगढ़, दिल्ली और दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली शीर्ष प्रदर्शनकर्ता हैं।
- राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड I राज्यों के प्रदर्शन को 6 मापदंडों पर रैंक करता है। ये मापदंड हैं- (1) डिस्कॉम का प्रदर्शन (2) ऊर्जा की पहुंच, वहनीयता और विश्वसनीयता (3) स्वच्छ ऊर्जा पहल (4) ऊर्जा दक्षता (5) पर्यावरणीय स्थिरता; और (6) नई पहल।

फिनक्लुवेशन

डाक विभाग के तहत 100% सरकारी स्वामित्व वाली इकाई इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने 21 अप्रैल, 2022 को 'फिनक्लुवेशन' (Fincluvation) पहल शुरू करने की घोषणा की।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह वित्तीय समावेशन के लिए सॉल्यूशन्स के सह-सृजन और नवाचार के लिए फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने की एक संयुक्त पहल है।

- फिनक्लुवेशन वित्तीय समावेशन के लिए लक्षित सार्थक वित्तीय उत्पादों के निर्माण की दिशा में स्टार्ट-अप समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए एक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म बनाने के लिए उद्योग की प्रथम पहल है।
- फिनक्लुवेशन सहभागी स्टार्टअप्स के साथ समावेशी वित्तीय समाधानों को सह-सृजित करने के लिए IPPB का एक स्थायी प्लेटफॉर्म होगा।

GK/GS तथ्यावलोकन

✧ भारत में आम आदमी के लिए सबसे सुलभ, किफायती और भरोसेमंद बैंक बनाने की दृष्टि से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की स्थापना संचार मंत्रालय के डाक विभाग के तहत, भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100% इक्विटी के साथ की गई है। इसे 1 सितंबर, 2018 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था।

बैटरी अदला-बदली नीति का मसौदा

सरकारी थिंक-टैंक नीति आयोग ने 21 अप्रैल, 2022 को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 'बैटरी अदला-बदली नीति' (Battery swapping policy) का मसौदा जारी किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इसके तहत, इसने अन्य उपायों के साथ-साथ अदला बदली योग्य (स्वैपेबल) बैटरी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को प्रोत्साहन देने, अदला बदली योग्य बैटरी बनाने वाली कंपनियों को सब्सिडी, एक नया 'बैटरी-एज-ए-सर्विस' (battery-as-a-service) बिजनेस मॉडल और अंत:प्रचालनीय बैटरी (interoperable batteries) के मानकों का प्रस्ताव दिया है।

राष्ट्रीय

सीमा दर्शन परियोजना

'सीमा दर्शन परियोजना' (Seema Darshan project) के हिस्से के रूप में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल, 2022 को गुजरात के नडाबेट में भारत-पाकिस्तान सीमा दर्शन स्थल का लोकार्पण किया।

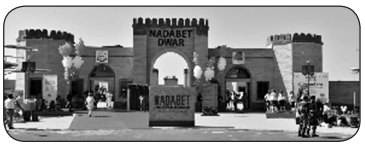

महत्वपूर्ण तथ्य: नडाबेट उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत-पाक सीमा पर स्थित है।

- नडाबेट सीमा दर्शन स्थल पंजाब के वाघा-अटारी बॉर्डर की तर्ज पर बनाया गया है।
- यह बहुउद्देशीय पर्यटन परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में पूरी हुई।
- सीमा दर्शन परियोजना का उद्देश्य लोगों को सीमाओं पर सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के जीवन और कार्यों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करना है।
- सीमा दर्शन परियोजना गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग और बीएसएफ गुजरात फ्रंटियर की एक संयुक्त पहल है।
- सीमा दर्शन परियोजना के तहत 125 करोड़ रुपये की लागत से सभी प्रकार की पर्यटन सुविधाओं और अन्य विशेष आकर्षणों का विकास किया गया है।

मुख्य आकर्षण: इसके प्रमुख आकर्षणों में से एक बीएसएफ सैनिकों द्वारा दैनिक परेड होगी।

- राष्ट्र की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों की स्मृति में 'अजय प्रहरी' नामक एक स्मारक बनाया गया है।
- पर्यटक नडाबेट में भारतीय सेना और बीएसएफ के विभिन्न हथियारों जैसे सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, टी-55 टैंक, आर्टिलरी गन, टॉरपीडो, विंग ड्रॉप टैंक और मिग-27 विमान भी देख सकेंगे।

प्रधानमंत्री संग्रहालय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल, 2022 को भारत के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान शुरू किया गया यह संग्रहालय, स्वतंत्रता के पश्चात अपने प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान के माध्यम से लिखी गई भारत की गाथा का वर्णन करता है।

- 271 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित प्रधानमंत्री संग्रहालय स्वतंत्रता के बाद से भारत के प्रत्येक प्रधानमंत्री की विचारधारा अथवा कार्यकाल से इतर देश के प्रति उनके योगदानों के लिए एक श्रद्धांजलि है।

- संग्रहालय ब्लॉक I के रूप में नामित तत्कालीन तीन मूर्ति भवन को ब्लॉक II के रूप में नामित नवनिर्मित भवन के साथ एकीकृत किया गया है।
- दो ब्लॉकों का कुल क्षेत्रफल 15,600 वर्ग मीटर से अधिक है। संग्रहालय में 43 गैलरी हैं।

GK/GS तथ्यावलोकन

✧ 'संग्रहालय का लोगो' राष्ट्र और लोकतंत्र के प्रतीक धर्म चक्र को धारण करने वाले भारत के लोगों के हाथों का प्रतिनिधित्व करता है।

वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में 4जी सेवाएं

27 अप्रैल, 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा स्थलों पर 2जी मोबाइल सेवाओं को 4जी में अपग्रेड करने के लिए एक सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष (Universal Service Obligation Fund) परियोजना को मंजूरी दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस परियोजना के चरण-I में 1,884.59 करोड़ रुपये (करों और शुल्कों को छोड़कर) की अनुमानित लागत से 2,343 वामपंथी उग्रवाद साइट्स को 2जी से 4जी मोबाइल सेवाओं में अपग्रेड करने की परिकल्पना की गई है।

- इसमें पांच साल के लिए संचालन और रख-रखाव शामिल है। हालांकि, बीएसएनएल अपनी लागत पर अगले पांच वर्षों के लिए इन साइटों का रख-रखाव करेगा। यह काम बीएसएनएल को सौंपा जाएगा क्योंकि ये साइट बीएसएनएल की हैं।
- मंत्रिमंडल ने 541.80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर पांच साल की अनुबंध अवधि से अधिक विस्तारित अवधि के लिए बीएसएनएल द्वारा वामपंथी उग्रवाद चरण-I के 2जी साइटों के संचालन और रखरखाव लागत के वित्तपोषण को भी मंजूरी दी है।

अंतरराष्ट्रीय

छठा भारत–जर्मनी अंतर–सरकारी परामर्श

तीन यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई, 2022 को जर्मनी पहुंचें।

महत्वपूर्ण तथ्य: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने बर्लिन में छठे भारत–जर्मनी अंतर–सरकारी परामर्श की सह–अध्यक्षता की।

- 2011 में शुरू किया गया, 'अंतर–सरकारी परामर्श' एक विशिष्ट द्विवार्षिक तंत्र है, जो द्विपक्षीय मुद्दों को व्यापक स्तर पर समन्वय करने में दोनों सरकारों को मदद करता है।
- छठा भारत–जर्मनी अंतर–सरकारी परामर्श रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने जर्मनी में आयोजित होने वाले जी–7 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया है।
- प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर स्कोल्ज ने हरित और सतत विकास साझेदारी की स्थापना के संयुक्त घोषणा पत्र (Joint Declaration of Intent) पर हस्ताक्षर किए।
- इस साझेदारी में सतत विकास लक्ष्य और जलवायु कार्रवाई पर भारत–जर्मनी सहयोग के लिए एक संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है, जिसके तहत जर्मनी ने 2030 तक 10 बिलियन यूरो की नई और अतिरिक्त विकास सहायता की अग्रिम प्रतिबद्धता पर सहमति व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित किया।

GK/GS तथ्यावलोकन

✧ 2021 में, भारत और जर्मनी ने राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 साल पूरे किए और वर्ष 2000 से दोनों देश रणनीतिक साझेदार रहे हैं।

भारत–जर्मनी समझौते

2 मई, 2022 को प्रधानमंत्री की जर्मनी यात्रा के दौरान छठे भारत–जर्मनी अंतर–सरकारी परामर्श के अवसर पर कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

महत्वपूर्ण समझौते: इंडो–जर्मन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर आशय की संयुक्त संयुक्त घोषणा;

- कृषि पारिस्थितिकी पर आशय की संयुक्त घोषणा;
- हरित और सतत विकास साझेदारी पर आशय की संयुक्त घोषणा;
- तीसरे देशों में त्रिकोणीय विकास सहयोग परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर आशय की संयुक्त घोषणा;
- विदेश मंत्रालय और जर्मन विदेश कार्यालय के बीच वर्गीकृत सूचनाओं के आदान–प्रदान और पारस्परिक संरक्षण पर समझौते की स्थापना तथा एक सीधा कूटभाषा आधारित संपर्क स्थापित करने के लिए समझौते की स्थापना पर आशय की संयुक्त घोषणा;
- अक्षय ऊर्जा साझेदारी के संबंध में भारत–जर्मन विकास सहयोग;
- व्यापक प्रवास और आवागमन साझेदारी पर समझौते की शुरुआत पर संयुक्त घोषणा;
- भारत से कॉर्पोरेट अधिकारियों और कनिष्ठ अधिकारियों के उन्नत प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग जारी रखने पर आशय की संयुक्त घोषणा;
- तथा वन परिदृश्य के लिए पूर्वावस्था की प्रप्ति पर आशय की संयुक्त घोषणा।

GK/GS तथ्यावलोकन

✧ जर्मनी 21 अरब डॉलर से अधिक के द्विपक्षीय व्यापार के साथ यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।

चीन की वैश्विक सुरक्षा पहल

चीनी अधिकारियों के अनुसार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा पेश की गई एक नई 'वैश्विक सुरक्षा पहल' अमेरिकी हिंद–प्रशांत रणनीति और क्वाड (भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान समूह) का मुकाबला करेगी।

महत्वपूर्ण तथ्य: शी जिनपिंग ने चीन में बोआओ फोरम को संबोधित करते हुए, 'आधिपत्यवाद, सत्ता की राजनीति और गुट टकराव' के खिलाफ चेतावनी देते हुए, एक वैश्विक सुरक्षा पहल का प्रस्ताव रखा।

- वैश्विक सुरक्षा पहल के मॉडल के तहत चीन 'एकतरफावाद का विरोध करेगा और समूह की राजनीति और गुट टकराव को ना कहेगा।'
- यह मॉडल पश्चिमी प्रतिबंधों को संदर्भित करने के लिये 'एकतरफा प्रतिबंधों और लंबे समय तक अधिकार क्षेत्र के उपयोग का विरोध करेगा'।

विज्ञान–पर्यावरण

ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2021

अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (UN-FAO) और गैर-सरकारी और गैर-लाभकारी संगठन 'आर्बर डे फाउंडेशन' द्वारा मुंबई और हैदराबाद को 'ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2021' (Tree Cities of the World 2021) के रूप में मान्यता दी गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य: दो भारतीय शहरों ने 'स्वस्थ, लचीले और खुशहाल शहरों के निर्माण में शहरी वृक्षों को उगाने और हरियाली बनाए रखने की प्रतिबद्धता' के लिए मान्यता हासिल की है।

- हैदराबाद को लगातार दूसरे साल इस सूची में शामिल किया गया है। मुंबई को पहली बार सूची में स्थान प्राप्त हुआ है।
- 21 देशों के कुल 138 शहर 'ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2021' सूची का हिस्सा हैं।
- सूची में अमेरिका के 37 शहर हैं, जबकि यूनाइटेड किंगडम के 19 और कनाडा के 18 शहर हैं, जो दर्शाता है कि विकसित देशों में हरित शहरों की हिस्सेदारी अधिक है।

ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड: यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और अमेरिकी गैर-लाभकारी संगठन आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है।

- यह कार्यक्रम उन शहरों और कस्बों को मान्यता देने का एक अंतरराष्ट्रीय प्रयास है, जो अपने शहरी वनों और वृक्षों का ठीक से रखरखाव करने और उनका स्थायी रूप से प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिये प्रतिबद्ध हैं।
- ट्री सिटी या वृक्ष शहर के रूप में मान्यता के लिए, एक समुदाय को पांच मुख्य मानकों को पूरा करना होता है- उत्तरदायित्व स्थापित करना, नियम निर्धारित करना, आपके पास क्या है यह जानना, संसाधनों का आवंटन करना तथा उपलब्धियों का जश्न मनाना।

भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र

20 अप्रैल, 2022 को असम के जोरहाट में भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र (India's first pure green hydrogen plant) का शुभारंभ किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: ऑयल इंडिया लिमिटेड ने असम में अपने जोरहाट पंप स्टेशन पर 10 किलोग्राम प्रति दिन की स्थापित क्षमता के साथ भारत के पहले 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र की शुरुआत की।

- इस संयंत्र को रिकॉर्ड 3 महीने के समय में चालू किया गया है।
- हरित हाइड्रोजन, जिसमें जीवाश्म ईंधन को बदलने की क्षमता है, अक्षय ऊर्जा जैसे पवन या सौर ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादित हाइड्रोजन गैस को दिया गया नाम है।
- संयंत्र मौजूदा 500 किलोवॉट सौर संयंत्र द्वारा 100 किलोवॉट अनियन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (Anion Exchange Membrane: AEM) इलेक्ट्रोलाइजर संरचना का उपयोग करके उत्पन्न बिजली से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करता है।

- भारत में पहली बार AEM तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है।
- इस संयंत्र से भविष्य में हरित हाइड्रोजन का उत्पादन 10 किलो प्रतिदिन से बढ़ाकर 30 किलो प्रतिदिन होने की उम्मीद है।
- कंपनी ने प्राकृतिक गैस के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के सम्मिश्रण और ऑयल इंडिया लिमिटेड के मौजूदा बुनियादी ढांचे पर इसके प्रभाव पर आईआईटी गुवाहाटी के सहयोग से एक विस्तृत अध्ययन शुरू किया है।

GK/GS तथ्यावलोकन

✧ हाइड्रोजन गैस, जो जलने पर कार्बन डाइ-ऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करती है, का उपयोग परिवहन, बिजली उत्पादन और औद्योगिक गतिविधियों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है।

भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022

केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल, 2022 को भारतीय अंटार्कटिका विधेयक, 2022 लोक सभा में पेश किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस विधेयक का उद्देश्य अंटार्कटिका में उन क्षेत्रों पर गतिविधियों की एक श्रृंखला को विनियमित करने के लिए नियमों का एक समूह निर्धारित करना है, जहां भारत ने अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं।

विधेयक के प्रावधान: यह अंटार्कटिका की यात्राओं और गतिविधियों के साथ-साथ महाद्वीप पर मौजूद लोगों के बीच उत्पन्न होने वाले संभावित विवादों को विनियमित करने की परिकल्पना करता है।

राज्य समाचार

लद्दाख

कृषि विभाग लद्दाख को मिला लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021

21 अप्रैल, 2022 को केंद्र-शासित प्रदेश लद्दाख के 'कृषि विभाग' को वर्ष 2021 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'लद्दाख ग्रीनहाउस परियोजना' के लिए 'नवाचार-राज्य' श्रेणी में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए लद्दाख के सचिव रविंदर कुमार को पुरस्कार प्रदान किया।
- पुरस्कार में एक ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 20 लाख रुपए का नकद पुरस्कार शामिल है।
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के लेह स्थित 'उच्च उन्नतांश अनुसंधान रक्षा संस्थान' (Defence Institute of High Altitude Research: DIHAR) द्वारा विकसित ग्रीनहाउस तकनीक को 2019 में लद्दाख कृषि विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया था।
- यह ग्रीनहाउस तकनीक लेह और कारगिल जिलों में लद्दाख ग्रीनहाउस परियोजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है।

लद्दाख के लेह जिले के 'ग्या-ससोमा' गांव में सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन

लद्दाख में 3 अप्रैल, 2022 को लेह जिले के 'ग्या-ससोमा' (Gya-Sasoma) गांव में सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया।

- लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, लेह के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी पार्षद ताशी ग्यालसन ने इस सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया।
- सामुदायिक संग्रहालय लद्दाख की युवा पीढ़ियों के लिए अपनी पहचान और इस क्षेत्र को समझने के लिए आगंतुकों के लिए एक केंद्र होगा।
- संग्रहालय में पारंपरिक उपयोगी वस्तुएं, वस्त्र, पोशाकें और ग्या-ससोमा के दैनिक जीवन की प्राचीन वस्तुएं मुख्य आकर्षण हैं।
- ग्या ऊपरी लद्दाख का पहला गांव और सबसे पुरानी बस्ती है और यह लेह-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है।

जम्मू-कश्मीर

'अवसर' पोर्टल

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 11 अप्रैल, 2022 को 'अवसर' पोर्टल (Avsar portal) लॉन्च किया।

- इस पोर्टल का उद्देश्य क्षेत्र में युवाओं को उपलब्ध नौकरी के अवसरों के बारे में रियलटाइम में जानकारी प्रदान करना है।
- अवसर पोर्टल का लक्ष्य मिशन यूथ द्वारा 'कनेक्ट टू अपॉर्चुनिटीज इनिशिएटिव' (Connect to Opportunities Initiative) के तहत वर्ष 2022 में 10,000 से अधिक नौकरियां प्रदान करना है। पहल के हिस्से के रूप में, मिशन यूथ ने जम्मू-कश्मीर के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए विजन इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- यह विभिन्न कॉर्पोरेट, राष्ट्रीय और बहु-राष्ट्रीय कंपनियों को जम्मू-कश्मीर के युवाओं से जोड़ेगा।
- 'कनेक्ट टू अपॉर्चुनिटीज इनिशिएटिव' के तहत युवाओं के लिए प्लेसमेंट सेल स्थापित किए जाएंगे।
- उद्यमी युवाओं के लिए सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए केंद्र-शासित प्रदेश के सभी आईटीआई और अन्य तकनीकी संस्थान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में रोपवे परियोजनाएं

26 अप्रैल, 2022 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, सिरमौर और बिलासपुर जिलों में सात रोपवे (रज्जु मार्ग) परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

- हिमाचल प्रदेश में अभिनव परिवहन सॉल्यूशंस के रूप में रोपवे के विकास के लिए शरोपवेज एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एचपी लिमिटेड' और 'नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड' के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

सार–संक्षेप

चर्चित व्यक्ति

अमित शाह

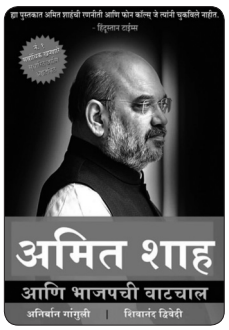

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 26 अप्रैल, 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर एक मराठी पुस्तक का विमोचन किया, जो उनकी राजनीतिक यात्रा का वर्णन करती है।

- 'अमित शाह आणि भाजपची वाटचाल' (Amit Shah Ani Bhajapachi Vatchal) नामक पुस्तक में शाह के जीवन एवं राजनीतिक यात्रा और भाजपा के संगठन में उनके योगदान का दस्तावेजीकरण किया गया है।
- मूल रूप से डॉ. अनिर्बान गांगुली और शिवानंद द्विवेदी द्वारा लिखित पुस्तक 'अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी' (Amit Shah and the March of BJP) का मराठी में अनुवाद डॉ. ज्योस्तना कोल्हाटकर ने किया है।

विनोद राय

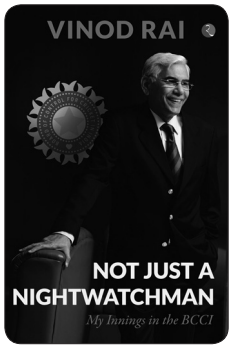

विनोद राय द्वारा 'नॉट जस्ट ए नाइटवॉचमैन: माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई' (NOT JUST A NIGHTWATCHMAN: My Innings in the BCCI) शीर्षक से एक नई किताब का लेखन किया गया है। इसे 'रूपा' प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है।

- यह किताब बीसीसीआई की प्रशासकों की समिति (सीओए) के अध्यक्ष के रूप में विनोद राय के 33 महीने के कार्यकाल के बारे में है।
- उन्होंने अपनी किताब में विराट कोहली और अनिल कुंबले के बीच रिश्तों में खटास का जिक्र किया है।
- ज्ञात हो कि इस विवाद के चलते 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद अनिल कुंबले ने भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच पद से इस्तीफा दे दिया था।
- विनोद राय भारत के पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) और बाहरी लेखा परीक्षकों के संयुक्त राष्ट्र पैनल के पूर्व अध्यक्ष हैं।
- विनोद राय की कुछ अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें 'नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट: द डायरी ऑफ द नेशन्स कॉन्शियस कीपर' (Not Just an Accountant: The Diary of the Nations Conscience Keeper) और 'रीथिंकिंग गुड गवर्नेंस: होल्डिंग टू अकाउंट इंडियाज पब्लिक इंस्टीट्यूशंस' (Rethinking Good Governance: Holding to Account India's Public Institutions) हैं।

निधन

जे डी रिंबाई

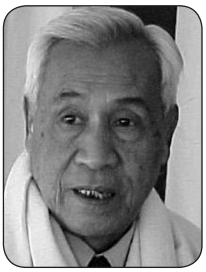

मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री जे डी रिंबाई का 21 अप्रैल, 2022 को निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे।

- उन्होंने 1983 में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया और जिरांग निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मेघालय विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए।
- वे 1993, 1998 और 2003 में लगातार तीन बार जिरांग से विधायक के रूप में फिर से चुने गए। 1993 में, वे मेघालय विधान सभा के अध्यक्ष चुने गए।
- उन्हें मुख्यमंत्री डी.डी. लापांग (2003–2006) का वफादार माना जाता था। 2006 में लापांग के नेतृत्व में असंतोष के बाद, उन्होंने एक वर्ष के लिए 2006 में मेघालय के मुख्यमंत्री का पद संभाला था।

प्रफुल्ल कर

महान संगीत निर्देशक, उड़िया गायक और गीतकार प्रफुल्ल कर का 17 अप्रैल, 2022 को निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे।

- उन्होंने 1962 में 'श्री श्री पतिता पबाना' के साथ उड़िया फिल्म उद्योग में एक पेशेवर गायक के रूप में शुरुआत की।
- 1975 में, उन्होंने फिल्म 'ममता' में एक संगीतकार के रूप में अपनी यात्रा शुरू की।
- प्रफुल्ल कर को कला के क्षेत्र में वर्ष 2015 में 'पद्म श्री' से सम्मानित किया गया था।

पत्र–पत्रिका संपादकीय

इस अंक में विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित लेखों के आधार पर संपादकीय तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी छात्रों को प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा से संबंधित विश्लेषणात्मक प्रश्नों की तैयारी में मदद करना है।

हाइड्रोजन के माध्यम से ऊर्जा स्वतंत्रता

हाल में जारी भारत की हरित हाइड्रोजन नीति ने कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान किया है जैसे कि खुली पहुंच, अंतर-राज्यीय पारेषण शुल्क की छूट, बैंकिंग, समयबद्ध मंजूरी, आदि, और इससे भारत के ऊर्जा संक्रमण (energy transition) को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नए युग के ईंधन, हाइड्रोजन को 'ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए भारत के प्रवेश द्वार' के रूप में जाना जाता है। भविष्य के ऊर्जा परिदृश्य में हाइड्रोजन की बहुआयामी भूमिका है, चाहे वह ऊर्जा भंडारण हो, लंबी दूरी का परिवहन हो या औद्योगिक क्षेत्र को कार्बन मुक्त करना हो। लगातार बढ़ती बिजली की मांग, हाइड्रोजन निर्माण की उच्च लागत और पानी की कमी भी एक चुनौती बन सकती है।

मांग पक्ष पर, पांच-चरणीय रणनीति तैयार की जानी चाहिए। प्रारंभिक मांग पैदा करने के लिए, पर्याप्त प्रोत्साहन के साथ परिष्कृत उद्योगों जैसे रिफाइनिंग और उर्वरक को एक अधिदेश (Mandate) दिया जाना; दूसरा, ग्रीन स्टील और ग्रीन सीमेंट के साथ साथ कम उत्सर्जन वाले हाइड्रोजन-आधारित उत्पादों का निर्माण करने वाले उद्योगों को सरकारी नीतियों द्वारा प्रोत्साहन; तीसरा, प्राकृतिक गैस के साथ हाइड्रोजन का सम्मिश्रण; फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए, समर्पित गलियारों पर हाइड्रोजन ईंधन स्टेशनों की योजना; और अंत में, कार्बन टैरिफ की अवधारणा को यूरोपीय देशों की तर्ज पर पेश करने की आवश्यकता। आपूर्ति पक्ष की ओर अनुसंधान एवं विकास में निवेश को गति प्रदान करने की आवश्यकता है; दूसरा, 15 एमएमटी संपीडित बायोगैस के उत्पादन लक्ष्य के साथ सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन (SATAT) योजना का लाभ हाइड्रोजन के साथ लिया जाना है।

हाइड्रोजन के साथ, भारत पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने में विश्व का नेतृत्व कर सकता है। हाइड्रोजन एक नए भारत की नींव रख सकता है, जो ऊर्जा-स्वतंत्र होगा; एक वैश्विक जलवायु नेतृत्वकर्ता और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा शक्ति होगा। **स्रोत- द हिंदू**

ध्वनि प्रदूषण पर उत्तर प्रदेश की पहल

प्रासंगिक अदालत के आदेशों में दोहराए गए ध्वनि प्रदूषण मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की पहल स्वागत योग्य है। यह राज्य सरकार की शोर (ध्वनि प्रदूषण) जैसे स्वास्थ्य और पर्यावरणीय खतरों से निपटने की प्रतिबद्धता का संकेत देती है। सरकार को उन स्थानों की सूची सार्वजनिक करनी चाहिए, जहां बिना अनुमति के चलते लाउडस्पीकरों को हटाना पड़ा और जिनका डेसिबल स्तर कम करना पड़ा। इस तरह, यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि मानदंडों को लागू करने में कोई राजनीतिक भेदभाव न हो या इसके परिणामस्वरूप किसी का उत्पीड़न न हो।

बढ़ता हुआ ध्वनि का स्तर (डेसिबल) शहरीकरण और औद्योगिक गतिविधि का हिस्सा है। लेकिन नागरिक समझ की कमी भी एक कारण है। यातायात और औद्योगिक प्रक्रियाओं से डेसिबल के स्तर को कम करने के लिए नवाचारों, प्रौद्योगिकी और शमन प्रयासों की आवश्यकता है। लेकिन लाउडस्पीकरों, साउंड एम्पलीफायर (Sound amplifiers), सार्वजनिक संबोधन प्रणालियों द्वारा किए गए शोर को कम करना आसान है। ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000, जिसे अंतिम बार 2010 में संशोधित किया गया था, सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए स्पष्ट नियम निर्दिष्ट करता है। राज्य सरकार को सभी हितधारकों द्वारा शोर मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए, न कि केवल धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग करने वालों से। इसे त्योहारों/उत्सवों के दौरान एक विशेष समय सीमा के भीतर डेसिबल को कभी-कभार बढ़ाने के लिए विशेष परमिट पर विचार करना चाहिए। इस अभियान के सफल होने के लिए सरकार की निष्पक्षता में विश्वास महत्वपूर्ण है। प्रशासन को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वह बिना किसी भय या पक्षपात के बिना शासन करे, विधि के शासन और इसके समान इस्तेमाल के प्रति प्रतिबद्धता करे। यह तब अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रायोगिक मॉडल के रूप में काम कर सकता है। **स्रोत- द इकनॉमिक टाइम्स**

स्वास्थ्य देखभाल हेतु आधुनिक पारंपरिक विकल्पः डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन

गुजरात के जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन (जीसीटीएम) की स्थापना एक बड़ा कदम है, जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा के 2030 लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। दुनिया की लगभग 80% आबादी पारंपरिक चिकित्सा पर निर्भर है। इसके बावजूद, साक्ष्य और आंकड़ों में पारंपरिक चिकित्सा को आधार बनाने का बहुत कम प्रयास किया गया है। अधिकांश पारंपरिक चिकित्सा प्राप्त ज्ञान और घरेलू उपचार पर आधारित है। डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन चार रणनीतिक क्षेत्रों पर काम करके इसे बदलने के लिए एक ठोस कदम है- साक्ष्य और प्रज्ञता (evidence and learning); डेटा और वैश्लेषिकी (data and analytics);